वाई. स्लीबेचेन ई. टी. सी.

बनाम

सुपरिंटिंग इंजीनियर डब्ल्यू. आर. ओ./पीडब्ल्यू. डी. और अन्य

(सिविल अपील सं। 7164-7166/2014)

4 अगस्त, 2014।

[जे. चेलामेश्वर और ए. के. सिकरी, जे. जे.]

फरमानः

सहमति आदेश मध्यस्थता पुरस्कार-में चुनौती दी गई जिला न्यायालय लंबित याचिकाएं, वार्ता विफल रही -हालांकि, जब याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं, तो ठेकेदार ने पेशकश की उसके दावों को और कम करने के लिए-द्वारा स्वीकार किया गया प्रस्ताव नियोक्ताओं की ओर से पेश सरकारी वकील और, तदनुसार, जिला न्यायालय द्वारा पारित एक सहमति आदेश नियोक्ता द्वारा इस आधार पर अपील कि उसका अधिवक्ता नहीं था किसी भी समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत-उच्च न्यायालय की सहमति आदेश को दरकिनार करते हुए-आयोजितः कुछ नहीं लाया गया है उत्तरदाताओं द्वारा यह दिखाने के लिए कि अधिवक्ता नहीं था ऐसा समझौता करने के लिए अधिकृत-अन्यथा भी, उत्तरदाताओं को जिल न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करना चाहिए था आदेश पारित होने के

तुरंत बाद समझौता आदेश, लेकिन यह नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय था द्वारा पारित सहमति आदेश को दरकिनार करना उचित नहीं है जिला न्यायाधीश-इस तरह की सहमति डिक्री एक के रूप में काम करती है रोकने और पार्टियों और उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी था इसके बाद एक विचार याचिका लेकर इससे बाहर न निकलें कि इसका वकील इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं था उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया और सहमति दी गई जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया गया-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस. 34 और 37-एस्टोपेल।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

ओ. 23, आर. 3 आर/डब्ल्यू ओ. 3, आर. 4-समझौता आदेश-मध्यस्थता जिला न्यायालय में चुनौती दिए गए पुरस्कार-सरकारी प्लीडर द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नियोक्ता के लिए उपस्थित होना किसी भी समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करना जिस पर आदेश के उचित अनुपालन में पारित किया जा सकता है ओ. 23, आर. के प्रावधान 3 और इस तरह का आदेश पूरी तरह से है वैध-एक पक्ष की ओर से कार्य करने के लिए एक वकील का अधिकार ओ. 3, आर. 1 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। 1 -तत्काल मामले में, सरकारी प्लीडर कानूनी रूप से प्रवेश करने का हकदार था अपीलार्थी-ठेकेदार और उसके लिखित के साथ

समझौता अपीलार्थी द्वारा दायर ज्ञापन पर समर्थन किया जा सकता है उत्तरदाता की वैध सहमति के रूप में माना जाता है-स्वयं नियोक्ता।

अपीलकर्ताओं-ठेकेदारों को तीन पुरस्कार दिए गए थे उत्तरदाताओं-नियोक्ताओं द्वारा अनुबंध। विवाद पक्षों और अंततः मध्यस्थता पुरस्कारों के बीच उत्पन्न हुआ पारित कर दिए गए। उत्तरदाताओं-नियोक्ताओं ने चुनौती दी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिकाओं में उक्त पुरस्कार। लंबित याचिकाएं, बातचीत पक्षों और ठेकेदार के बीच खोज की गई थी अंततः, 9.1.2009 पर आयोजित बैठक में, 5 प्रतिशत पर सहमति बनी। 40 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल राशि में कमी ब्याज राशि में कमी। हालांकि, जैसा कि नियोक्ताओं ने मूलधन में 10 प्रतिशत की कटौती पर जोर दिया राशि, बातचीत विफल हो गई और कब याचिकाएं दायर की गईं 9.4.2011 पर अदालत में सूचीबद्ध थे, अपीलार्थी आया इस प्रभाव के लिए ज्ञापन के साथ आगे बढ़ें कि इसके अलावा 9.1.2009 पर मूलधन से 5 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव राशि और 40 प्रतिशत ब्याज को छोड़ने के लिए, वह भी इच्छुक था पुरस्कार राशि पर आगे अर्जित ब्याज को छोड़ना 9.1.2009 के बाद। यह प्रस्ताव सरकार के सामने आया निष्पक्ष रूप से अभिवादक और उन्होंने सरकार-नियोक्ता की ओर से ज्ञापनों पर लिखित समर्थन किया कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। तदनुसार, कहा गया कि समझौता, याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की यह तर्क देते

हुए कि जिला में सरकारी वकील उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और खारिज कर दिया जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित:

1.1 एकमात्र मैदान जो प्रबल रहा है उच्च न्यायालय की अपीलों को स्वीकार करने में जिला न्यायाधीश के आदेशों के विरुद्ध प्रतिवादी हैं कि सरकारी प्लीडर द्वारा अधिकृत नहीं था रिकॉर्ड पर चलता है। सबसे पहले, यह होना चाहिए ध्यान रखें कि कुछ भी सामने नहीं आया है उत्तरदाता जो दिखाएँगे कि अधिवक्ता था इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं। जिस पर के समक्ष प्रस्तुत अपील के आधारों का अवलोकन उत्तरदाताओं द्वारा और यहां तक कि काउंटर में भी उच्च न्यायालय इस न्यायालय के समक्ष दाखिल हलफनामा, कोई आरोप नहीं है सरकारी प्लीडर के खिलाफ किसी भी प्रकार का। जिस पर इसके विपरीत, एक स्पष्ट कथन दिया गया है कि मान लें कि प्रत्यर्थी ने कोई पहल नहीं की है जिला सरकार के प्लीडर के खिलाफ कार्यवाही "। इसके अलावा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ भी एक नहीं है एक अभिवचन का अंश यह समझाते हुए कि सरकार कैसे प्लीडर सहमति दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं था या कि वह किसी भी तरह से अधिकार का अभाव था। यह दूर भी नहीं है किसी भी आधार पर सुझाव दिया कि सरकार प्लीडर ने अनुचित तरीके से

काम किया। इसके विपरीत जो चाहा जाता है सुझाव दिया जाना यह है कि समझौते की विफलता थी, या कि कोई समझौता दर्ज नहीं किया गया था या उस पर सहमति नहीं बनी थी न्यायालय के समक्ष, जो अभिलेख के विपरीत है अदालत और निर्णय में दर्ज किए गए बयान जिला न्यायालय और, इसलिए, एक के रूप में अस्वीकार्य चुनौती का मैदान। [पैरा 15] [1063-ए-जी] एस. सी. आर 8: (1982) 2 एस. सी. सी. 463-निर्भर

1.2. इसके अलावा, द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था इसके तुरंत बाद जिला न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी समझौते के संदर्भ में फरमानों का पारित होना, या यहाँ तक कि इसके बाद, समझौता आदेश को वापस लेने के लिए याचिका कि इस तरह का समझौता अस्वीकार्य था क्योंकि सरकारी वकील किसी भी समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं था इस तरह का समझौता। इसके बजाय, अपील दायर की गई थी उच्च न्यायालय। उत्तरदाताओं को संपर्क करना चाहिए था पहली बार में ट्रायल कोर्ट, क्योंकि यह ट्रायल जज है जिनके समक्ष समझौता दर्ज किया गया था और वह उन घटनाओं से अवगत था जिनके कारण समझौता आदेश हुआ, वह इस पहलू से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में था। [पैरा 16] [1065-ए-डी]

1.3 इसके अलावा, एक पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील है किसी भी शर्त पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम

समझौता जिस पर एक डिक्री पारित की जा सकती है ओ 23 र 3 सी. पी. सी. और ऐसी डिक्री पूरी तरह से वैध है। प्राधिकरण ने एक पक्ष की ओर से कार्य करने के लिए एक वकील का स्पष्ट रूप से दिया जाता है ओ. 3 में, आर. 1, सीपीसी। ओ. 3, आर. के प्रावधानों के अनुसार, एक बार वकील को उसके द्वारा वकील/प्राधिकरण की शक्ति मिलती है मुवक्किल किसी मामले में पेश होता है, उसे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलता है अदालत में उसके मुवक्किल और मामले का संचालन। इसके अलावा, यद्यपि ओ. 23, आर. 3 लिखित में समझौता करने की आवश्यकता है और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित, अधिवक्ता के हस्ताक्षर उक्त प्रयोजनों के लिए वकील वैध है। पल भर में मामला, सरकारी प्लीडर कानूनी रूप से हकदार था अपीलार्थी के साथ समझौता करें और अपीलार्थी द्वारा दायर ज्ञापन पर उसका लिखित समर्थन करें प्रतिवादी की वैध सहमति के रूप में माना जा सकता है स्वयं। [पैरा 17 और 19] [1070-ए-सी; 1065-सी-ई; 1070-ए-बी]

बख्शी देव राज बनाम सुधीर कुमार 2011 (9) एससीआर 815: (2011) 8 एस. सी. सी. 679; और जिनेश्वरदास ((घ) एल. आर. और अन्य बनाम. श्रीमती. जगरानी और अन्र।, 2003 पूरक। (4) एस. सी. आर. 17: (2003) 11 एससीसी 372 -पर भरोसा किया।

1.4 तत्काल मामले में मध्यस्थता पुरस्कार दिए गए थे बहुत पहले अप्रैल और जून में अपीलार्थी के पक्ष में, 2006। हालाँकि, अपीलार्थी को अभी तक लाभ नहीं मिला है वहाँ से। उत्तरदाता नं. 1 उक्त पुरस्कारों को चुनौती दी सुलह अधिनियम, 1996 स 34 जब उक्त कार्यवाही थी लंबित है, उत्तरदाताओं खुद के साथ बाहर आया बातचीत करने और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करने के प्रस्ताव विषय हैं। हालाँकि अपीलार्थी त्याग करने के लिए सहमत हो गया ब्याज आदि के संदर्भ में पुरस्कार का बड़ा हिस्सा। उस समय वार्ता विफल रही क्योंकि उत्तरदाता 10 प्रतिशत चाहते थे मूल राशि में कमी जबकि अपीलार्थी केवल 5 प्रतिशत देने के लिए स्वीकार कर रहा था। अपीलार्थी अदालत में और रियायतें देने के लिए सहमत हुए जब मामला 9.4.2011 पर आया, उनके तीन ज्ञापनों में दिनांकित 6.4.2011 उस तारीख को दाखिल किया गया। ये ज्ञापन बताते हैं कि अपीलार्थी ने तीव्र होने के कारण उक्त प्रस्ताव दिया था अपने बैंकरों सहित अपने लेनदारों को संतुष्ट करें जिन्हें वह काफी राशि बकाया है। लेकिन इसके बाद भी निपटान फलदायी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पारित हुआ सहमत आदेश, इसके परिणामस्वरूप कानूनी उलझन हुई है और अपीलार्थी उक्त सहमति भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है राशि। [पैरा 21] [1070-जी-एच; 1071-ए-डी]

1.5 अतः इस न्यायालय की राय है कि -सहमति को दरकिनार करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश।

ऐसी सहमति डिक्री एक अवरोध के रूप में काम करती है और उस पर बाध्यकारी थी पक्ष जिनसे उत्तरदाता हस्तक्षेप नहीं कर सके एक विचार के बाद याचिका दायर करके कि उसका वकील था। इस तरह के समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और सहमति दी जाती है जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया जाता है। [पैरा 21-22] [1071-E-G]

केस लॉ रेफरेन्स

1983 (1) एस. सी. आर 8	उस पर भरोसा करें	पैरा 15
2011 (9) एससीआर 815	उस पर भरोसा करें	पैरा 17
2003 (4) पूरक। एस. सी. आर. 179	उस पर भरोसा करें	पैरा 18

सिविल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7164-7166/2014 से।

के 29.02.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से सी. एम. ए. में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ (एम. डी.) नं. 1455 तक 1457/ 2011,

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पी. वी. दिनेश, सिंधु टी. पी. उन्नीकृष्णन एस. नायर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुब्रमण्यम प्रसाद, एएजी, बी. बालाजी, आर. राकेश शर्मा, राजीव डी., अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. अनुमति दी गई।

2. दिनांकित सामान्य निर्णय 29.02.2012 द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन सिविल विविध निर्णय लिए हैं मध्यस्थता की धारा 37 (1) (बी) के तहत दायर अपील और वे तीन अपीलें यहाँ उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई थीं। 28.04.2011 दिनांकित आदेशों को चुनौती देना जो पारित किए गए थे प्रधान जिला न्यायाधीश, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु द्वारा। एकल आदेश द्वारा अपीलों के निपटारे के कारण थे पक्षकारों की समानता के साथ-साथ उक्त तीन अपीलों में शामिल मुद्दा।

3. ऐसा हुआ कि अपीलार्थी, जो एक है इंजीनियरिंग ठेकेदार को तीन अनुबंध दिए गए थे यहाँ उत्तरदाताओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) गुंडार के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए तिरुनेलवेली जिले में जलाशय प्रणाली के लिए बोलियां थीं कॉल किया गया और जिसमें याचिकाकर्ता सफल हो गया एक अनुबंध मूल्य के लिए काम निष्पादित करने के लिए बोलीदाता रु.: 80,14,605 / -दिनांकित पंजीकृत समझौते के तहत 2.04.1998 पूरा करने के लिए 15 महीने की अवधि के भीतर अनुबंध कार्य।

(ii) पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए तिरुनेलवेली जिले में करुप्पानधी जलाशय प्रणाली बोलियाँ बुलाई गईं और जिसमें याचिकाकर्ता बन गया सफल बोलीदाता अनुबंध मूल्य पर कार्य निष्पादित करने के लिए

दिनांकित पंजीकृत समझौते के तहत Rs.55,82,633/-का 20.07.1998 पूरा करने के लिए 18 महीने की अवधि के भीतर अनुबंध काम करते हैं।

(iii) तिरुनेलवेली जिले में कन्नड़ एनीकट और चैनल रीच-1 के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए बोलियाँ बुलाई गईं और जिसमें याचिकाकर्ता बन गया सफल बोलीदाता अनुबंध मूल्य पर कार्य निष्पादित करने के लिए पंजीकृत समझौते के तहत Rs.69,24,038/-का 28.07.1998 पूरा करने के लिए 26 महीनों की अवधि के भीतर अनुबंध कार्य।

4. बीच कुछ विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए इन सभी अनुबंधों से संबंधित पक्ष। इसके अनुसार उन स्थलों पर जहाँ कार्य किए जाने थे अपीलार्थी और इसके अलावा, कई अन्य उल्लंघन थे विभाग द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध तीन अनुबंधों के तहत। अपीलार्थी ने अपने दावे किए तीनों अनुबंधों का सम्मान। विभाग ने नियुक्त किया श्री वेलु एक मामले में मध्यस्थ के रूप में और श्री एस. कृष्णमूर्ति अन्य दो मामलों में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद विवादों का न्यायनिर्णयन, तीनों मामलों में निम्नलिखित प्रभाव से पुरस्कार पारित किए गएः भुगतान या प्राप्ति।

(I) अवार्ड दिनांक 09.06.2006 अपीलार्थी के पक्ष में श्री वेलू रुपए 52,90,776 मैं ब्याज 18 % वार्षिक दर से 9 6 2006 तक प्राप्ति भुगतान तक या अनुभूति।

(ii) अवार्ड दिनांक 25 4 2006 जिसके द्वारा अपीलार्थी कुल रुपए 39,74,964 मैं ब्याज 18% % दर से अवार्ड की दिनांक से प्राप्ति भुगतान तक या अनुभूति।

(iii) अपीलार्थी के पक्ष में दिनांकित पुरस्कार 25.04.2006 जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 को एक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 42,56,419/-पी. ए. अवार्ड की तारीख से भुगतान तक या अनुभूति।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दाखिल करके सभी अवार्ड को चुनौती दी अधिनियम की धारा 34 के तहत तीन याचिकाएं, जिन्हें रद्द करने की मांग की गई है ये पुरस्कार। अपीलार्थी ने याचिकाएँ का विरोध करते हुए अपने जवाब दाखिल किए। इन सभी याचिकाओं को प्रधान जिला न्यायाधीश, तिरुनेलवेली के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जबकि ये कार्यवाहियाँ थीं प्रधान जिला न्यायाधीश, के समक्ष लंबित सरकार लोक निर्माण विभाग ने दिनांक 02.12.2008 पर पत्र जारी किया जिसके द्वारा उसने अपने अधिकारियों को अपीलार्थी के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया मध्यस्थता पुरस्कार राशि के निपटान के लिए। तदनुसार, वहाँ 19.12.2008

पर पार्टियों के बीच बैठकें थीं और 09.01.2009 अदालत के बाहर समझौता करने के लिए। अधिकारीगण, अधीक्षण अभियंता सहित, के साथ चर्चा की थी अपीलार्थी, जिसमें अपीलार्थी से कम करने का अनुरोध किया गया था 40 % तीनों कार्यों के लिए मूल राशि से सम्मानित राशि स्वतंत्र मध्यस्थता पुरस्कारों के अंतर्गत आता है। इसके बजाय ठेकेदार 40 प्रतिशत ब्याज कम करने के लिए आगे आया तीनों कार्यों के लिए कुल प्रदत्त राशि पर उपार्जित, विशेष रूप से तीनों के संबंध में ब्याज के संदर्भ में काम करता है, जो मुख्य पुरस्कार के लिए 12.81% तक काम करता है तीन पुरस्कारों के अंतर्गत आने वाली राशि। हालांकि, अधीक्षण अभियंता ने इसमें और कमी करने पर जोर दिया मूल राशि। अंततः चैंबर में आयोजित बैठक में। 9.1.2009 पर अधीक्षण अभियंता, ठेकेदार प्रधान पुरस्कार में 10 प्रतिशत की कटौती करने के लिए कहा गया था अर्जित किया। हालाँकि, अपीलकर्ता केवल 5 प्रतिशत की कमी पर सहमत हुआ। मूल राशि में 40 प्रतिशत की कमी के अलावा ब्याज राशि। द्वारा ली गई उपरोक्त स्थिति के कारण पक्षों, बातचीत फलीभूत नहीं हो सकी। न्यायालय के समक्ष लंबित तीन पुरस्कारों, सरकार के प्रधान सचिव ने लिखा है कि संबंधित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदनों को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए 9.1.2009 दिनांकित पत्र।

6. हालाँकि, मामले अदालतों में बने रहे किसी न किसी कारण से। जब उन्हें न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया था 09.04.2011 पर, अपीलार्थी

एक के साथ आगे आया इस आशय का ज्ञापन कि, प्रस्ताव के अलावा पूर्वगामी ब्याज के लिए 09.01.2009 पर बातचीत के दौरान 40 प्रतिशत पर, वह आगे अर्जित ब्याज को छोड़ने के लिए भी तैयार था 09.01.2009 के बाद पुरस्कार राशि। यह प्रस्ताव दिखाई दिया सरकारी वकील के प्रति निष्पक्ष रहें। उन्होंने लिखा है उक्त ज्ञापन पर समर्थन, की ओर से सरकार ने कहा कि उसे इस ज्ञापन पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप इस समझौते पर कार्रवाई करते हुए, याचिकाएं आंशिक रूप से थीं अनुमति दी गई और मध्यस्थों के पुरस्कारों को संशोधित किया गया जिसके तहत पुरस्कार राशि में से मूलधन में 5 प्रतिशत की कमी की जाएगी। राशि का आदेश दिया गया था। 40 प्रतिशत की कटौती के अलावा 09.01.2009 तक दिया गया ब्याज; इससे अधिक उपार्जित कुल ब्याज उस अवधि को भी माफ कर दिया गया था। हालांकि, पुरस्कार की तारीख से अर्थात 25.04.2006 से 09.01.2009 तक, ब्याज की गणना 18 प्रतिशत पी. ए. पर की गई थी जहाँ से ब्याज राशि में 40 प्रतिशत की कमी की गई थी दिया गया।

7. मुख्य तथ्यों को दोहराने के लिए, समझौता बातचीत करता है के उदाहरण पर पक्षों के बीच हुआ उत्तरदाता स्वयं अन्वेषण करने का अपना इरादा व्यक्त करते हैं इसके दिनांकित 02.12.2008 पत्र के अनुसार निपटान की संभावना। इसके लिए कुछ बैठकें आयोजित की गईं। अपीलार्थी ब्याज के पर्याप्त हिस्से का 5 प्रतिशत भी छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी। मूल

राशि। तथापि, अधीक्षण अभियंता, पक्ष में दी गई मूल राशि में 10 प्रतिशत की कमी चाहते थे। अपीलार्थी का यह इस अंतर के कारण है कि समझौता उस समय वार्ता विफल रही और सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया धारा 34 के तहत आवेदन। योग्यता पर अधिनियम। हालांकि, जब मामला जिला न्यायाधीश के सामने आया 9.4.2011 पर, अपीलार्थी पूरे ब्याज को छोड़ने के लिए सहमत हो गया 09.01.2009 के बाद भी अर्जित, इसके अलावा रियायतें जो अपीलार्थी द्वारा पहले ही दी जा चुकी थीं और ऊपर लिखा है। जब सरकारी वकील था अपीलार्थी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव का सामना करते हुए, उन्होंने एक विचार रखा कि यह एक बहुत ही उचित प्रस्ताव था और इस पर एक समर्थन किया स्वयं को इस प्रभाव के लिए प्रस्तुत करें कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी उसी को स्वीकार करने के लिए। इसके परिणामस्वरूप पुरस्कार में संशोधन किया गया जिला न्यायाधीश द्वारा सहमत शर्तों के संदर्भ में, उनके द्वारा तीनों याचिकाओं में 28.04.2011 दिनांकित आदेश।

8. हालाँकि, उत्तरदाताओं ने इन आदेशों को चुनौती धारा 37 के तहत अपील दायर करके विद्वान जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में अधिनियम का, मुख्य रूप से इस आधार पर कि सरकार ने जिन शर्तों का समर्थन किया था, उन पर कभी सहमति नहीं जताई थी। सरकारी प्लीडर, जितना, वह कभी नहीं था इस उद्देश्य के लिए अधिकृत। यह तर्क दिया गया था कि

अनुपस्थिति में सरकारी प्लीडर के पक्ष में किसी भी प्राधिकरण का, उनके द्वारा दिए गए समझौते का समर्थन सरकार बाध्यकारी नहीं था।

9. जब मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, तब भी उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य को एक बार फिर समझौते की संभावना पर विचार करें और मामला इस उद्देश्य के लिए स्थगित कर दिय। हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख पर, उत्तरदाताओं के वकील ने एक बयान दिया कि सरकार को समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे चाहते थे गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का मामला। उच्च न्यायालय, तदनुसार, मामले को सुना और विवादित फैसले इसे दरकिनार कर दिया प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश तीनों में पारित किए गए याचिकाएं, इसे दायर किए गए आवेदनों के गुण-दोष पर निर्णय लेने का निर्देश देना अधिनियम की धारा 34 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा। यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री का अभाव कि सरकारी प्लीडर था समझौता दर्ज करने के लिए अधिकृत, इस तरह का समझौता था उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी नहीं। उच्च न्यायालय का निर्णय इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने वैधता पर सवाल उठाते हुए इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

10. यह अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि वह गंभीर वित्तीय संकट में था और उसे संतुष्ट करने की आवश्यकता थी उनके बैंकरों सहित लेनदारों और उक्त को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों में,

उन्होंने 06.04.2011 दिनांकित अलग-अलग ज्ञापन दायर किए विद्वान जिला न्यायाधीश के सामने यह कहते हुए कि वह तैयार था इसके बाद दी गई राशि पर उपार्जित ब्याज को छोड़ दें। 09.01.2009 इस दौरान किए गए पहले के प्रस्ताव के अलावा 09.01.2009 पर बातचीत में यह प्रावधान किया गया है कि राशि इस प्रकार है एकमुश्त यानी एक ही किस्त में भुगतान किया जाना और उक्त भुगतान 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। में उक्त ज्ञापन में अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि उक्त प्रस्ताव है -अपीलार्थी के लड़ने के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया योग्यता पर याचिका। आगे छोड़ने के इस तरह के प्रस्ताव के जवाब में तीन पुरस्कार राशियों के लिए 10.01.2009 से ब्याज, 09.04.2011, सरकारी प्लीडर, की ओर से प्रत्यर्थी ने एक लिखित समर्थन किया कि उपरोक्त ज्ञापनों के तहत प्रस्ताव वार्ता के अनुसार है 09.01.2009 पर किया गया और पूरी ब्याज राशि छोड़ने की पेशकश की गई 09.01.2009 से सरकार के लिए फायदेमंद था। वह भी। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार को इन ज्ञापनों पर कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि जब सरकारी प्लीडर ऊपर बताए गए तरीके से उपरोक्त समर्थन किया,और इसके परिणामस्वरूप इसके आधार पर सहमत आदेश पारित किया गया पक्षों के बीच समझौता हुआ, यह उत्तरदाताओं के लिए वहाँ से पीछे हटने के लिए खुला नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं को यह तर्क देने से रोक दिया गया कि सरकारी प्लीडर को ऐसा करने का

अधिकार नहीं था बयान। यह भी तर्क दिया गया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई थी प्रत्यर्थियों द्वारा उस अधिवक्ता के विरुद्ध लिया गया जिसके पास था। उसकी ओर से पेश हुए जो सरकार के रूप में बने रहे प्लीडर।

11. उत्तरदाताओं के लिए सीखा हुआ परामर्श, दूसरी ओर हाथ, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को उचित ठहराया प्रस्तुत करना कि यह सरकारी प्लीडर के लिए खुला नहीं था बिना किसी प्राधिकरण के अपीलार्थी के प्रस्ताव को स्वीकार करें, अधिक विशेष रूप से, जब यह पहले से ही द्वारा तय किया गया था सरकार, 09.01.2009 दिनांकित पत्र के माध्यम से, मामलों को लड़ने के लिए गुणों पर। इसलिए, द्वारा किया गया ऐसा समर्थन उत्तरदाताओं की ओर से सरकारी वकील नहीं था उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी।

12. हमने अपना सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है पक्षकारसभक वकील द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित तर्क। अपीलार्थी ने अभिलेख पर 3 की प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं। प्रधान जिला न्यायालय के समक्ष जिसका अनुमोदन किया गया था सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी किया गया। ये सभी ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए शब्द समान रूप से लिखे गए हैं और प्रासंगिक हैं इसके उद्धरण से निम्नलिखित पढ़ा जा सकता हैः

"अब आवश्यकताओं पर विचार करते हुए और इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव का सम्मान करना वार्ता के दौरान दिए गए उपरोक्त प्रस्ताव से 09.01.2009 यह प्रतिवादी आगे जाने की पेशकश कर रहा है 09.01.2009 के बाद पुरस्कार पर उपार्जित ब्याज, प्रदान किया गया याचिकाकर्ता निम्नलिखित का निरीक्षण करता है और कार्य करता है तदनुसारः

1. भुगतान एकमुश्त और एकमुश्त में किया जाता है किश्त।

2. भुगतान आज से तीन महीने के भीतर किया जाता है।

यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी है अपने गंभीर वित्तीय संकट के कारण उपरोक्त प्रस्ताव देना और अपने सहित अपने लेनदारों को संतुष्ट करने की वश्यकता बैंकर। इसलिए उपरोक्त प्रस्ताव पूर्वाग्रह के बिना है। याचिका का विरोध करने के लिए प्रथम प्रतिवादी के

अधिकार के लिए इस न्यायालय के समक्ष पूरी तरह से योग्यता के आधार पर लंबित है। यह है। तदनुसार प्रस्तुत किया गया।

अप्रैल 2011 के इस छठे दिन की तारीख।"

13. सरकारी प्लीडर का समर्थन ये 3 ज्ञापन, जो समान रूप से शब्दबद्ध हैं, में लिखा है

इसके अंतर्गतः

"प्रतिलिपि प्राप्त की। यह ज्ञापन 09.01.2009 बातचीत के साथ प्रस्ताव इसके अनुसार है।। इसके अलावा ब्याज लाभ 09.01.2009 से सरकार के लिए। इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। इस ज्ञापन के लिए।

09-04-2011, सरकारी प्लीडर"

14. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकार अधिवक्ता प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए ने न केवल अपीलार्थी के प्रस्ताव को हित में पाया गया सरकार

और सरकार के लिए फायदेमंद, लेकिन एक ही पहले हुई वार्ताओं के अनुसार भी था 09.01.2009 पर पार्टियों के बीच। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दलों ने पहले एक अवसर पर बातचीत की थी न्यायालय के बाहर विवादों का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजना में। उस चरण में, याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी पुरस्कारों के तहत उन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ था। हालांकि, उत्तरदाता/सरकार और अधिक चाहते थे रियायतें जिन पर अपीलार्थी ने उस समय सहमति नहीं दी थी समय। इसके परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हुआ और उत्तरदाताओं ने फैसला किया गुण-दोष पर अधिनियम की धारा 34 के तहत अपनी आपत्तियों के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि, जब मामला पहले सामने आया न्यायालय ने 09.04.2011 पर और अपीलार्थी ने इसके बाद अधिनिर्णय के तहत उपार्जित आगे के ब्याज को छोड़ने का प्रस्ताव दिया। 09.01.2009, और उसी पर अदालत में चर्चा की गई थी, यह प्रस्ताव सरकारी वकील के लिए आकर्षक पाया गया जिनका विचार था कि इस तरह का प्रस्ताव हित में था उत्तरदाताओं और बातचीत के अनुसार भी था पहले 09.01.2009 पर आयोजित। उन्होंने इसे स्वीकार किया और न्यायालय ने दोनों के बीच समझौते के संदर्भ में आदेश पारित किए पार्टियाँ।

15. एकमात्र मैदान जो उच्च न्यायालय के साथ प्रबल रहा है प्रतिवादियों की अपीलों को स्वीकार करने में उपरोक्त आदेश यह है कि सरकारी वकील नहीं था प्रत्यर्थियों द्वारा इस तरह के समझौते में प्रवेश

करने के लिए अधिकृत। इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है, ऐसे परिदृश्य में जो रिकॉर्ड पर चलता है। सबसे पहले, इसे रखा जाना चाहिए ध्यान रखें कि उत्तरदाताओं द्वारा कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जो दिखाएगा कि अधिवक्ता प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं था सरकारी वकील के खिलाफ किसी भी प्रकार का। इसके विपरीत, एक स्पष्ट बयान दिया गया है कि "की कार्रवाई प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी इस संबंध में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था। ज़िले के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है सरकारी प्लीडर "। इसके अलावा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ तक कि एक अभिवचन का एक अंश भी नहीं है जिसमें बताया गया है कि कैसे सरकारी प्लीडर सहमति दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं था या कि उसके पास किसी भी तरह से अधिकार की कमी थी। यह दूर भी नहीं है इनमें से किसी भी आधार पर सुझाव दिया कि सरकारी प्लीडर उन्होंने अनुचित तरीके से काम किया। इसके विपरीत, क्या होने की कोशिश की जाती है सुझाव दिया गया है कि समझौते की विफलता थी, या कि इससे पहले कोई समझौता या सहमति दर्ज नहीं की गई थी न्यायालय, जो न्यायालय के अभिलेख के विपरीत है और जिला न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित वक्तव्य, और इसलिए चुनौती के आधार के रूप में अस्वीकार्य। इस संबंध में, हम निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे के मामले में इस न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र राज्य v. रामदास नायक (1982) 2 एस. सी. सी. 463।

"4. जब हमने विद्वान वकील का ध्यान आकर्षित किया उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई रियायत के लिए सामान्य, श्री ए. के. सेन, जो उच्च न्यायालय के समक्ष महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए और उनके पक्ष में दलीलों का नेतृत्व किया वहाँ उत्तरदाता और जो श्री अंतुले की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के लिए उपस्थित हुए इससे पहले कि हम हस्तक्षेप करें और विरोध करें कि उन्होंने कभी नहीं किया ऐसी कोई रियायत और हमें लिखित रूप से पढ़ने के लिए आमंत्रित किया उच्च न्यायालय में उनके द्वारा प्रस्तुतियाँ। हम हैं। डर है कि हम जांच शुरू नहीं कर सकते हैं कि क्या उच्च न्यायालय में हुआ। यह बस नहीं किया जाता है। सार्वजनिक नीति हमें रोकती है। न्यायिक शिष्टाचार हमें रोकता है। के मामले न्यायिक अभिलेख निर्विवाद हैं। वे खुले नहीं हैं सन्देह हो रहा है। न्यायाधीशों को अखाड़े में नहीं घसीटा जा सकता है। " निर्णयों को केवल प्रतिवाद के रूप में नहीं माना जा सकता है मुकदमेबाजी का खेल"। सोमसुंदरन बनाम सुब्रमण्यममें लॉर्ड एटकिंसन के अनुसार हम बयान को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में क्या दर्ज किया अदालत में हुआ। हम इस कथन की अनुमति नहीं दे सकते कि न्यायाधीशों का

बार में दिए गए बयानों या शपथ पत्र और अन्य साक्ष्यों द्वारा खंडन किया जाना। यदि न्यायाधीश कहते हैं कि निर्णय कि कुछ किया गया था, कहा गया था या स्वीकार किया गया था उनके सामने, यह विषय पर अंतिम शब्द होना चाहिए। सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि तथ्य के बयान सुनवाई में क्या हुआ, निर्णय में दर्ज किया गया न्यायालय के, इस प्रकार बताए गए तथ्यों के निर्णायक हैं और नहीं इस तरह के बयानों का कोई भी हलफनामा या अन्य माध्यम से खंडन कर सकता है। सबूत। यदि कोई पक्ष सोचता है कि अदालत में घटनाएँ एक निर्णय में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, यह है ' पदधारी, पार्टी पर, जबकि मामला अभी भी ताजा है न्यायाधीशों के मन, बहुत न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिन्होंने इस तथ्य को दर्ज किया है कि बयान उनके आचरण के संबंध में एक बयान दिया गया था कि गलती से किया गया था। लार्ड बकमास्टर के अनुसार मधुसूदन बनाम। चंदेरवती यही एकमात्र तरीका है अभिलेख को ठीक किया गया। अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो मामला वहाँ अवश्य ही समाप्त होना चाहिए। निश्चित रूप से एक दल फिर से सक्रिय हो सकता है और एक अपीलीय न्यायालय उसे दुर्लभ में

अनुमति दे सकता है और रियायत से वापस भेजने के लिए उपयुक्त मामले इस आधार पर कि रियायत गलत तरीके से दी गई थी कानून की सराहना और घोर अन्याय का कारण बना; लेकिन, हो सकता है कि वह बनाने के तथ्य पर सवाल न उठाए। निर्णय में दर्ज रियायत"।

16. यह भी इंगित करना उचित है कि यहाँ भी, नहीं उत्तरदाताओं द्वारा जिले के समक्ष आवेदन दायर किया गया था समझौते में आदेश पारित होने के तुरंत बाद न्यायालय समझौता आदेश को वापस लेने के लिए शर्तें, या उसके बाद भी इस दलील के साथ कि इस तरह का समझौता अस्वीकार्य था सरकारी प्लीडर किसी भी मामले में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं था इस तरह का समझौता। इसके बजाय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। अदालत। हमारी राय है कि उत्तरदाताओं को होना चाहिए पहली बार में निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि यह मुकदमा है न्यायाधीश जिनके समक्ष समझौता दर्ज किया गया था और जैसा कि वह उन घटनाओं की जानकारी थी जिनके कारण समझौता आदेश हुआ, वह था इस पहलू से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में।

17. इसके अलावा, हम पाते हैं कि आदेश के प्रावधानों के अनुसार III नियम 4, एक बार जब वकील को वकील/प्राधिकरण की शक्ति मिल जाती है उसके मुवक्किल द्वारा किसी मामले में पेश होने के लिए, उसे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलता है अदालत में उसके मुवक्किल और मामले का संचालन। इसके अलावा, बख्शी देव राज बनाम। सुधीर कुमार, (2011) 8 एससीसी 679, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि सी. पी. सी. का आदेश XXIII नियम 3 एक समझौते को लिखित रूप में और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है, अधिवक्ता/वकील का हस्ताक्षर उक्त के लिए मान्य है। उद्देश्य। इस पहलू पर विस्तृत चर्चा जो आगे बढ़ती है उक्त निर्णय में और हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इसके अंतर्गतः

> "25. अब हमें वकील की भूमिका पर विचार करना होगा समझौता होने के बारे में अदालत को रिपोर्ट करना। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि आदेश 23 नियम 3 सी. पी. सी. के संदर्भ में, समझौता या समझौता लिखित में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उपरोक्त प्रावधान के प्रभाव और वकील की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है। बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम उनिओन बैंक ऑफ इंडिया में इस न्यायालय द्वारा। ने कहा कि भारत

में अदालतों ने वकीलों की पारंपरिक भूमिका और उनकी ओर से कार्य करने के लिए निहित अधिकार की सीमा और प्रकृति को लगातार मान्यता दी अपने ग्राहकों के लिए। श्री रंजीत कुमार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वकालतनामा (अनुलग्नक आर-3) की प्रति और उसमें सामग्री। वकालतनामा में संलग्न शब्द वकील को उनकी ओर से कई कार्य करने में सक्षम बनाएँ उसका मुवक्किल जिसमें वापस लेना या समझौता मुकदमा या मामला शामिल है अदालत के समक्ष विचाराधीन। में विभिन्न खंड वकालतनामा निःसंदिग्ध रूप से सलाह देने की शक्ति देता है अधिकतम ब्याज के साथ कार्य करें जिसमें एक में प्रवेश करना शामिल है समझौता या समझौता।

26. पैरास में निम्नलिखित अवलोकन और निष्कर्ष 37, 38 और 39 प्रासंगिक हैंः

"37. हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह विवेकपूर्ण होगा। वकील के लिए निहित अधिकार पर कार्य नहीं करने के लिए सिवाय इसके कि कब माँग करने

वाली परिस्थितियों की आवश्यकता के कारण समझौते द्वारा मुकदमे का तत्काल समायोजन या समझौता और पक्ष के हस्ताक्षर नहीं हो सकते हैं और जल्दी। संचार, ऐसी आकस्मिकता हो सकती है शायद ही कभी उत्पन्न होता है। एक बुद्धिमान और सावधान सलाह इसमें कोई संदेह नहीं होगा। आवश्यक प्राधिकारी के साथ पहले से खुद को तैयार करें ऐसी सभी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए लिखित रूप में व्यक्त किया गया आदेश दें कि न तो उसका अधिकार और न ही सत्यनिष्ठा कभी संदेह हुआ। यह आवश्यक सावधानी सुरक्षा करेगी वकील की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसे बनाए रखनाकानूनी पेशे की प्रतिष्ठा और गरिमा।

38. पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका को ध्यान में रखते हुए सामान्य कानून प्रणाली में परामर्श, और बुराई की मांग की गई सी. पी. सी. (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा संसद द्वारा सुधार किया जाना अर्थात् निश्चितता की प्राप्ति और शर्तों को कम करके मामलों का त्वरित निपटान पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लेखन के लिए समझौता, और अनुमति देना मामलों को भी समझने के लिए समझौता

डिक्री वाद के विषय से बाहर होना, लेकिन संबंधित दलों के लिए, विधायिका, की अनुपस्थिति में नहीं कर सकते हैं इस तरह के प्रभाव के लिए शब्दों को व्यक्त करें, ऐसा माना जाए कि द्वारा पक्षों को समझौता करने की अनुमति नहीं दी गई। उनके कारण में या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों द्वारा परामर्श। ऐसी कोई भी धारणा इसके साथ असंगत होगी अनिश्चितताओं और विस्तार को समाप्त करके न्यायालय में समझौते का दायरा।

39. पार्टी पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने का आग्रह करना। समझौता या समझौता अक्सर अनुचित होता है देरी, हानि और असुविधा, विशेष रूप से गैर-निवासी व्यक्ति। यह हमेशा सार्वभौमिक रहा है यह समझ में आया कि एक पक्ष हमेशा उसके अनुसार कार्य कर सकता है अधिकृत प्रतिनिधि। यदि कोई पावर-ऑफ-अटार्नी धारक है की ओर से कोई समझौता या समझौता कर सकते हैं उसका प्रधान, इसलिए सलाह दे सकता है, जिसके पास आवश्यकता है इस तरह की क्षमता को न पहचानना केवल बहुत कुछ नहीं है व्यक्तिगत रूप से पक्षों को असुविधा और नुकसान, लेकिन न्यायालय में कार्यवाही की प्रगति में देरी करना।

अगर विधायिका ने इस तरह के मौलिक बनाने का इरादा किया था अनावश्यक व्यय, यह स्पष्ट रूप से कहा गया होगा।"

27. जिनेश्वरदास बनाम। जगरानी इस न्यायालय को मंजूरी देते हुए बायराम पेस्टनजी मामले में लिया गया निर्णयः

"8..... कि इसके परिणामस्वरूप पारित कोई निर्णय या डिक्री अदालत के समक्ष सर्वसम्मति बनी, इसे हमेशा समझौता या समझौते पर पारित कहा नहीं जा सकता है और समायोजन। यह कभी-कभी एक निर्णय भी हो सकता है प्रवेश"।

28. जगतर सिंह बनाम परगट सिंह ने यह माना कि अपीलार्थी के वकील के पास बयान देने की शक्ति है पक्ष द्वारा अपील वापस लेने के निर्देश पर। उस मामले में, प्रतिवादी 1 उसमें, के बड़े भाई याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया और तीन भाई जो 4-5-1990 का फरमान था शून्य और शून्य जो अधीनस्थ द्वारा घोषित किया गया था न्यायाधीश, होशियारपुर 29-9-1993 पर।

याचिकाकर्ता इसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अतिरिक्त जिले के न्यायालय में एक अपील दायर की न्यायाधीश, होशियारपुर। वकील ने एक बयान दिया 15-9-1995 कि याचिकाकर्ता का आगे बढ़ने का इरादा नहीं था अपील के साथ। उसके आधार पर, अपील थी वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने चुनौती दी पुनरीक्षण में अपीलीय न्यायालय का आदेश। उच्च न्यायालय ने उसी की पुष्टि की जिसके कारण एसएलपी दाखिल करने की आवश्यकता पड़ी इस न्यायालय के समक्ष।

29. जगतर सिंह में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील मामले में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने अधिकृत नहीं किया था अपील वापस लेने के लिए वकील। यह आगे था यह तर्क दिया कि अदालत ने अपील स्वीकार करने के बाद वापस लिए गए के रूप में उसी को खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है सिवाय इसके कि की वैधता को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय लें विचारण न्यायालय का तर्क और निष्कर्ष या तो इससे सहमत या असहमत होना। उक्त बात को अस्वीकार करते हुए विवाद, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने वकील को अधिकृत नहीं किया था अपील वापस लें। अदालत ने याचिका स्वीकार करने के बाद उसे

वापस लिए जाने के रूप में खारिज करने की कोई शक्ति नहीं है सिवाय इसके कि की वैधता पर विचार करते हुए गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय लेना विचारण न्यायालय का तर्क और उसके साथ सहमत या असहमत होने वाले निष्कर्ष। हम में कोई बल नहीं पाते हैं विवाद। आदेश 3 नियम 4 सी. पी. सी. वकील को अधिकार देता है। मुक़दमे की कार्यवाही तक अभिलेख पर जारी रखना विधिवत समाप्त कर दिए जाते हैं। इसलिए, वकील के पास शक्ति है पार्टी के निर्देशों पर बयान देना अपील वापस लें। सवाल यह है कि क्या अदालत को योग्यता के आधार पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है आदेश के खिलाफ निर्णय से अपील की गई अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय? आदेश 23 नियम 1 (1) और (4) पक्ष को दायर किए गए दावे को छोड़ने की शक्ति दें। सी. पी. सी., यह अपील और अपीलीय पर समान रूप से लागू होता है न्यायालय के पास अपीलार्थी को की अनुमति देने की व्यापक शक्ति है। प्रत्यर्थी के खिलाफ अपनी अपील को या तो छोड़ दें राहत का पूरा या हिस्सा। इसके परिणामस्वरूप, हालांकि अपील आदेश 41 नियम 9 के तहत स्वीकार की गई थी, अनिवार्य रूप से अदालत के पास

अपील को खारिज करने की शक्ति है क्योंकि मामले के गुण-दोष में गए बिना वापस ले लिया गया और इसके नियम 11 के तहत इसका निर्णय लेना।

4. तदनुसार, हम मानते हैं कि द्वारा की गई कार्रवाई 3 नियम 4 सी. पी. सी. यदि वास्तव में वकील ने कार्रवाई नहीं की है पार्टी के हित में या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ, आवश्यक उपचार कहीं और है और प्रक्रिया निम्नलिखित न्यायालय द्वारा अपनाया गया, इसके अनुरूप है -सीपीसी के प्रावधान। हम में कोई अवैधता नहीं पाते हैं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

30. उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वकील जिसे एक पक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया था आदेश 3 नियम 4, वकील को जारी रखने का अधिकार देता है जब तक मुकदमे में कार्यवाही विधिवत नहीं हो जाती, तब तक रिकॉर्ड करें समाप्त कर दिया। इसलिए, वकील के पास यह शक्ति है कि पार्टी के निर्देशों पर एक बयान दें अपील वापस लें। ऐसी स्थिति में, वकील या तो वापस लेने के निर्देशों पर

बयान देना अपील या डिक्री के संशोधन के लिए अच्छी तरह से भीतर है उसकी क्षमता और यदि वास्तव में वकील ने कार्रवाई नहीं की है पार्टी का हित या उसके निर्देशों के विरुद्ध पक्षकार, आवश्यक उपाय कहीं और है। "

18. इसी तरह 2011 में, यह अदालत जिनेश्वरदास (डी) मेंऊघ एल. आर. और ओआरएस। वी. श्रीमती. जगरानी और अन्न।, (2003) 11: 372, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः

> "यदि कोई पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक कोई समझौता कर सकता है या अपने प्रधान की ओर से समझौता, तो सलाह दे सकते हैं, वकालतनामा द्वारा अपेक्षित प्राधिकरण के पास, अपने मुवक्किल की ओर से कार्य करें।

19. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में सरकार प्लीडर कानूनी रूप से समझौता करने का हकदार था दायर ज्ञापन पर अपीलार्थी और उसका लिखित समर्थन अपीलार्थी द्वारा एक वैध सहमति के रूप में माना जा सकता है स्वयं उत्तरदाता। इसलिए एक पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील किसी भी शर्त पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है समझौता जिस पर एक डिक्री उचित रूप से पारित की जा सकती है आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधानों का अनुपालन और डिक्री पूरी तरह से

वैध है। कार्य करने के लिए एक वकील का अधिकार किसी पक्ष की ओर से सिविल के आदेश III नियम 1 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्रक्रिया संहिता जो यहाँ नीचे निकाली गई है;

> "किसी भी अदालत में या उसके समक्ष कोई उपस्थिति, आवेदन या कार्य,कानून द्वारा बनाए जाने या किए जाने के लिए आवश्यक या अधिकृत ऐसे न्यायालय में पक्षकार, सिवाय जहां अन्यथा हो सकता है उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, पार्टी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा किया या किया जाए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, या एक वकील द्वारा, उपस्थित होना, आवेदन करना या उसकी ओर से जैसा भी मामला हो, कार्य करना।
>
> बशर्ते कि ऐसी कोई उपस्थिति, यदि न्यायालय ऐसा करता है, निर्देश, पार्टी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाए"।

20. इस मामले में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है और इसके द्वारा उजागर किए जाने की

आवश्यकता है हमें तर्क के समय, से एक प्रासंगिक प्रश्न पर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील कि क्या कोई कार्रवाई सरकारी प्लीडर के खिलाफ लिया गया था, विद्वान वकील यह स्वीकार करने में स्पष्ट थे कि न केवल कोई कार्रवाई की गई थी लिया गया, उक्त वकील के पैनल में बने रहे मामले। यह स्वयं दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने कोशिश की है इस तरह के विशाल को लेकर एक वैध समझौते से बाहर निकलें याचिका जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

21. यह एक ऐसा मामला है जिसमें मध्यस्थता पुरस्कार दिए गए थे बहुत पहले अप्रैल और जून, 2006 में अपीलार्थी का पक्ष। हालाँकि, अपीलार्थी को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वाई. दाखिल करके इन पुरस्कारों को चुनौती दी। अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन। जब ये कार्यवाही लंबित थी, उत्तरदाता स्वयं आए बातचीत के प्रस्ताव के साथ बाहर निकलें और सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता करने का प्रयास करें मामले, अन्यथा प्रशंसनीय निर्णय को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा ऐसे विवादों को निपटाने के लिए लिया गया जो पत्र से स्पष्ट है दिनांकित 02.08.2008। इसके बाद बातचीत हुई। हालांकि अपीलार्थी पुरस्कार के महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था। ब्याज आदि के संदर्भ में, उस समय वार्ता विफल रही क्योंकि उत्तरदाता मूल राशि में 10 प्रतिशत की कमी चाहते थे। साथ ही, जबकि अपीलार्थी केवल त्याग करना स्वीकार कर रहा था 5 % मूल राशि से। हो

सकता है, अपीलार्थी सहमत हो जाए मामला आने पर न्यायालय में और रियायतें देना 09.04.2011 पर दर्ज किए गए उनके 3 ज्ञापन दिनांकित 6.4.2011 को देखें तिथि. इन ज्ञापनों से पता चलता है कि अपीलार्थी ने दिया था उन्होंने कहा कि तीव्र वित्तीय संकट के कारण वे पीड़ित थे क्योंकि वह अपने बैंकरों सहित अपने लेनदारों को संतुष्ट करना चाहता था जिन पर उन्होंने काफी राशि बकाया रखी थी। अफ़सोस, इसके बाद भी समझौता फलीभूत हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सहमति पारित हुई आदेशों के परिणामस्वरूप इसके बाद भी कानूनी उलझन पैदा हुई है, और अपीलार्थी उक्त सहमति भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है राशि। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय पारित सहमति आदेश को दरकिनार करना उचित नहीं था विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा। इस तरह की सहमति डिक्री काम करती है एक अवरोध के रूप में और उन पक्षों पर बाध्यकारी था जिनसे उत्तरदाता एक के बाद एक विचार करके बाहर नहीं निकल सके याचिका कि उसका वकील इस तरह के मामले में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं था समझौता।

22. इन अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और इनमें से प्रत्येक अपील में इसकी मात्रा Rs.25,000/-निर्धारित की गई है।

राजेंद्र प्रसाद

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।**

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।